दिये है। कुछ विचारों को वह मानती है और कुछ को नहीं मानती है, उनको वह नाकाफी समझती है। उन पर हम फिर विचार करते है। वह विचार चल रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि वे चीजें अंडर एग्जेमिनेशन हैं। लेकिन बहुत सी बातों पर हम ने उनको सफाई दे दी है।

श्री हुकम चन्द कछवाय: हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई के समय जो पुर्जे अमरीका ने देने बन्द कर दिये थे क्या उसने उसकी पहले से सूचना दी थी और क्या उसके कारण थे, इसकी जांच करने की क्या सरकार ने कोशिश की थी? अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आप इस पर अंतिम निर्णय ले लेंगे?

Shri B. R. Bhagat: As it is well-known, suddenly there was a stoppage of supplies.

Mr. Speaker: Next question. Shri Indrajit Gupta. Absent. The next question has been transferred to the Home Ministry, to be answered on the 26th. Next question. Shri Y. S. Kushwah.

स्वेज नहर का बन्द किया जाना

+

*1179. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह:**
श्री आत्म दास:
डा० सूर्य प्रकाश पुरी:
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:
श्री रामावतार शर्मा:
श्री महन्त दिग्विजय नाथ:
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री:
श्री हुकम चन्द कछवाय:
श्री शिव कुमार शास्त्री:

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर के बन्द हो जाने से भारत तथा अन्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh (a) and (b). Yes, Sir. A statement was made by my colleague, the Defence Minister, on the 30th June that the closure of the Suez Canal is a matter of great concern to India and other countries affected as well as to the UAR. In this connection UAR Government have stated that they are unable to reopen the Canal so long as Israeli forces continue to occupy the east bank of the Canal and other Arab territories occupied by them.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह: : माननीय व्यापार मंत्री दिनेश सिंह जी अभी कर्नल नासर से मिलने काहिरा गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वेज नहर के बारे में भी उनके साथ चर्चा की या नहीं और क्या कोई रास्ता निकाला गया है कि भारत का जो अन्न स्वेज नहर के बन्द हो जाने की वजह से रुका हुआ है वह जल्दी भारत आ सके?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: क्या दिनेश सिंह जी की बातें नासर साहब के साथ जरूर हुई हैं लेकिन इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि आया स्वेज कैनाल के बारे में बात हुई है या नहीं हुई है। मेरा ख्याल है जरूर हुई होगी। लेकिन यू० ए० आर० का कहना यही है कि हम इसको नहीं खोल सकते हैं कुछ बजूहात के कारण से।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह: मैं जानना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में विदेश मंत्री जी क्या कार्यवही करने जा रहे हैं कि भारत का यह अन्न जल्दी से जल्दी भारत आ सके?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: इसका जवाब खाद्य मंत्री कई बार दे चुके हैं। हमारे जो

जहाज हैं, जो फूडस्टेनस ला रहे हैं तो दूसरे रास्ते से केप के रास्ते से आ रहे हैं। सिर्फ एक जहाज है जो इस नहर के अन्दर फसा हुआ है। उसके हाल ही में आने की सम्भावना नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर र हैं और देख रहे है कि इसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : भारत सरकार स्वयं इस बात को कहती है कि स्वेज नहर से हमारे जहाजों के न आ सकने के कारण प्रति वर्ष हमें लगभग 17 करोड़ से अधि॰ का बोझा अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। लगभग ऐसी स्थिति दूसरे देशों की भी होगी जो स्वेज नहर के रास्ते से अपना माल मंगाते हैं ऐसी स्थिति में क्या भारत सरकार अपनी पुरानी भूल का प्रायश्चित करते हुए इस बात का निश्चय करेगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्न को उठाया जाए कि स्वेज नहर अन्तर्राष्ट्रीय नहर हो जानी चाहिये ताकि भविष्य में किसी को फिर इस प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े ?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): That is precisely the question we have raised in the United Nations. The question we raised was, the Israeli troops who were on Egyptian territory should be withdrawn before any further talks could take place, and we had this in mind that so long as the Israeli troops were on the eastern bank of the canal, it would not be possible to open the canal. As my hon. friend knows, till yesterday firing was going on across the canal. The UN observers are about to be posted. But till we settle the question of withdrawal there is no possibility of opening of the canal. Therefore, our delegation and many other delegations concentrated on this point that as a first step before anything further was done the Israeli troops should be withdrawn and if they withdraw then the other steps would be taken to open the canal.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपने सवाल को आपको समझा पाया हूं लेकिन मंत्री महोदय को नहीं समझा पाया हू। स्वेज नहर के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन का मार्ग हो जाने का परिणाम केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अच्छा होगा, उनको भी इससे लाभ पहुंचेगा। भारत सरकार विश्व शांति की नीति में विश्वास करती है। लेकिन अपनी पुरानी भूलों का प्रायश्चित करते हुए क्या अब ये इजराइल की फौजें हट जायेंगी या और शान्ति की स्थापना हो जाएगी तो स्वेज नहर को अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में या दुनिया के सामने उपस्थित करेगी ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है और मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हू।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हिन्दी में हैं।

Shri M. C. Chagla: Sir, I agree entirely with my hon. friend that it is in the interest not only of India but of several countries that the Suez Canal should be reopened. But I do not understand which is the mistake for which we should repent, because what we have done in the United Nations is primarily for the purpose of clearing the Suez Canal and getting it reopened.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मैं व्यवस्था के प्रश्न उठाने का आदी नहीं हूं। मेरा प्रश्न स्पष्ट है। भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है कि स्वेज नहर को अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग माना जाए बजाय इसके कि उस पर एक ही देश का अधिकार रहे। इस बात का उत्तर विदेश मंत्री नहीं दे रहे हैं।

Shri M. C. Chagla: That question has not arisen. If it arises, the Government of India will give careful consideration to the implications of

the question. The present question is whether the Suez Canal should be reopened. We are concerned with the reopening of the Canal.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ: समाचार पत्रों से यह पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्न से पश्चिमी एशिया में समझौता हो गया है । क्या मैं जा सकता हूं कि क्या इस समझौते से हमें कुछ लाभ होगा और हमारा जो माल स्वेज नहर में रुका पड़ा है, उस को यहां लाने की सुविधा मिल सकेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: माननीय सदस्य ने जिस समझौते का जिक्र किया है, उस के मातहत सिर्फ यह हुआ है कि यू० एन० ओ० के आबजर्वर्ज स्वेज नहर के क्षेत्र में पहुंच गए हैं । उन के वहां जाने से स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू० ए० आर० की जो पहली शर्त है कि इसराईल के ट्रूप्स वहां से हट जायें, वह पूरी नहीं हुई है और इसराईल के ट्रूप्स अभी वहां ही मौजूद हैं । इसलिए हमें कोई सहूलियत या लाभ होने का सवाल अभी पैदा नहीं होता है ।

12 hrs.

QUESTION UNDER RULE 40

Action taken reports of the Public Undertakings Committee

Shri Madhu Limaye:
Shri George Fernandes:

Will the Chairman, Public Undertakings Committee be pleased to state:

(a) how many Action Taken Reports have they received from Government in regard to the recommendations made by the Public Undertakings Committee in its Reports during the Third Lok Sabha;

(b) how many of such Reports the Public Undertakings Committee have reviewed so far;

(c) whether these reports of reviews reveal any areas of disagreement;

(d) if so, a brief outline/summary of this disagreement;

(e) whether the Public Undertakings Committee have prescribed any time-limit for submitting the Action Taken Reports; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Chairman, Public undertakings Committee (Shri D. N. Tiwary): (a) Out of a total of 31 original Reports of the Committee on Public Undertakings, full replies to the following four reports have been received from the Government so far:

(i) 11th Report on the Rourkela Steel Plant of the Hindustan Steel Ltd.

(ii) 2nd Report on the Hindustan Insecticides Ltd.

(iii) 6th Report on the Fertilizer Corporation of India.

(iv) 8th Report on the Township and Factory Buildings of Public Undertakings.

Partial replies to the following five reports have been received from the Government so far:

(i) 1st Report on the National Building construction Corporation.

(ii) 4th Report on the Life Insurance Corporation.

(iii) 5th Report on the Oil & Natural Gas Commission

(iv) 28th Report on the Head Office of the Hindustan Steel Ltd.

(v) 31st Report on the Alloy Steel Project of the Hindustan Steel Ltd.

(b) Of the four Action Taken Reports, one has already been processed and presented to the Lok Sabha. The remaining three Reports are under consideration of the Committee.

(c) and (d). Area of agreement, disagreement between the Government and the Committee are brought